



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111 ]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 7, 2000/श्रावण 16, 1922

No. 111]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 7, 2000/SRAVANA 16, 1922

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2000

सं. टीएएमपी/8/2000—सामान्य.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार प्रयोक्ताओं द्वारा भुगतान में विलंब और पत्तन न्यास द्वारा धन-वापसी में विलंब पर दंडिक ब्याज निर्धारित करने से संबंधित प्राधिकरण के दिनांक 4 फरवरी, 2000 के आदेश के विरुद्ध कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निपटान करता है।

अनुसूची

मामला सं० टीएएमपी/8/2000—सामान्य

कलकत्ता पत्तन न्यास (सीपीटी) ...

आवेदक

आदेश

(जुलाई, 2000 के 19वें दिन को पारित किया गया)

इस प्राधिकरण ने 4 फरवरी, 2000 को एक आदेश पारित किया था, जोकि प्रयोक्ताओं द्वारा भुगतान में विलंब और पत्तन न्यासों द्वारा धन-वापसी में विलंब पर समान रूप से 24 प्रतिशत ब्याज अधिरोपित करने से संबंधित था। यह आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में 23 फरवरी, 2000 को राजपत्र सं० 20 द्वारा अधिसूचित किया गया था।

2.1 कलकत्ता पत्तन न्यास (सीपीटी) ने इस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि यह आदेश कानूनी रूप से मान्य नहीं है। सीपीटी ने मांग की है कि सभी महापत्तनों को सूचित करते हुए इस आदेश को अप्रभावी किया जाए/वापिस लिया जाए।

2.2

सीपीटी ने इस आदेश के विरुद्ध निम्नलिखित आपत्तियां उठाई हैं :-

- (i) एमपीटी अधिनियम के अध्याय-9 की धाराएं 112 से 119 दण्डों के अधिरोपण से संबंधित हैं। इन धाराओं में यह निर्धारित नहीं है कि भुगतान में विलंब पर दण्ड लगाया जाएगा।
- (ii) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में वसूल किया जाने वाला ब्याज, दण्ड के अधिरोपण की तरह नहीं माना जाता है। इसलिए, यह वर्तमान आदेश एमपीटी अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।
- (iii) टीएएमपी, एमपीटी अधिनियम की धारा 48 से 51 के अंतर्गत दरों के मान और शर्तों के विवरण तैयार करने के लिए प्राधिकृत है। अधिप्रभार की वापिसी, अधिनियम की धारा 55 के प्रावधानों के नियमानुसार है और इस धारा के अंतर्गत बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी समय अपने बिल में अधिप्रभार को माफ कर सकता है। अधिनियम की धारा 55 में अधिप्रभारों की वापिसी के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- (iv) यदि आवश्यक हो तो, केवल केन्द्रीय सरकार धारा 111 के अंतर्गत ऐसे मामलों में बोर्ड को निदेश दे सकती है।
- (v) वह शर्त, जिसमें अधिप्रभारों की वापिसी स्वीकार्य है, एमपीटी अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत निर्धारित की गई है। एमपीटी अधिनियम की धारा 55 में समाविष्ट शर्तें और टीएएमपी के आदेश में समाविष्ट शर्तें समान नहीं हैं।
- (vi) यह आदेश इस अधिनियम के प्रावधानों और एमपीटी अधिनियम की धारा 55 और 129 के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन है।

3. सीपीटी द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में उपलब्ध समग्र जानकारी और समग्र विचार-विमर्श पर आधारित निष्कर्ष के अनुसार निम्नलिखित स्थिति उभरती है :-

- (i) एमपीटी अधिनियम की धाराएं 112 से 119 (अर्थात् अध्याय-10; और, अध्याय-9 नहीं जोकि सीपीटी द्वारा उल्लिखित है) एमपीटी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अधिप्रभारों के अधिरोपण से संबद्ध है। सीपीटी ने सही उल्लेख किया है कि व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में वसूल किया जाने वाला ब्याज अधिप्रभार के अधिरोपण के समान नहीं माना जाता है। यह अम्यारोपित आदेश, सामान्य व्यापार प्रक्रिया के दौरान ब्याज में छूट के बारे में बताता है।
- (ii) एमपीटी अधिनियम की धारा 129 का सीपीटी का संदर्भ असंगत है। धारा 129 वायुयान से संबंधित अधिनियम में कुछ प्रावधानों पर लागू होने के बारे में है।
- (iii) अधिनियम की धारा 55 में पत्तन न्यास से अधिप्रभार की वापिसी के दावे की समय-सीमा का उल्लेख किया गया है। धारा 55 के अंतर्गत प्रावधान को निम्नवत पढ़ा जाए :-  
"बशर्ते कि बोर्ड अपने प्रस्ताव पर अपने बिलों में किसी भी समय अधिप्रभार छोड़ सकता है।"

शायद, सीपीटी 'किसी भी समय' शब्दों पर निर्भर है, जिसे वह अपने तर्क का आधार बना रहा है कि अधिप्रभार की वापिसी वह किसी भी समय प्राप्त कर सकता है। धारा 55 के

अंतर्गत प्रावधान, केवल बोर्ड को शक्ति प्रदान करता है कि वह दावेदार के आवेदन का बिना इंतजार किए स्वयं से अधिप्रभारों की वापिसी का निर्णय कर सकता है और ऐसे निर्णय में 6 माह की समय-सीमा लागू नहीं होती । धारा 55 के मुख्य खंड में 'किसी भी समय' शब्दों के लागू होने संबंधी सीपीटी की व्याख्या सही नहीं है ।

(iv) इसी प्रकार, प्राधिकरण एमपीटी, अधिनियम के कार्य-क्षेत्र से बाहर कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकता । अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट न होने पर सीपीटी भी कुछ भी वसूल नहीं कर सकता । सीपीटी पट्टा किरायों के भुगतान में देरी पर 18 प्रतिशत दंडिक ब्याज वसूल कर रहा है । सीपीटी ने हल्दिया में भूमि और भवन से संबंधित अपनी किराया अनुसूची में ऐसा दंडिक ब्याज लगाने के लिए एक प्रावधान शामिल किया है ।

(v) सीपीटी द्वारा प्रस्तावित यह अनुसूची इस प्राधिकरण द्वारा भी अनुमोदित है । सीपीटी अपनी किराए की अनुसूची में भुगतानों में देरी पर दंडिक ब्याज शामिल करने के प्रावधान का प्रस्ताव करते हुए यह मानता है कि :-

- देरी से भुगतान पर दंडिक ब्याज की वसूली में वृद्धि सामान्य व्यापार प्रक्रिया के संदर्भ में होगी;
- इसे शर्तों के विवरण में शामिल किया जा सकता, जिनके अधीन इसकी संपत्तियां प्रयोग की जाती हैं; और,
- यह प्राधिकरण इस प्रकार का आदेश दे सकता है ।

(vi) सीपीटी की दरों के मान (भूमि और भवनों के लिए) में उपर्युक्त शर्त केवल सीपीटी भूमि के बकायादार किरायदारों/पट्टाधारकों पर लागू है ! इस अभ्यारोपित आदेश में उल्लिखित है कि यह अधिभार दोनों पक्षों पर लागू होगा; और, पत्तन न्यास द्वारा प्रदत्त सेवाओं और/या पत्तन न्यास की संपत्तियों के प्रयोग के प्रसंग में होने वाले भुगतानों पर भी यह सिद्धांत (सीपीटी द्वारा स्वीकृत) लागू हो सकता है ।

(vii) यह मानना होगा कि इस आदेश का आशय दोनों पक्षों, अर्थात् पत्तन प्रयोक्ताओं और पत्तन न्यासों दोनों के लिए भुगतान हेतु एकसमान दंडिक ब्याज का निर्धारण करना है । अन्य शब्दों में, चाहे कोई भी समय-सीमा हो या दंडिक ब्याज दर निर्धारित की जाती है, ऐसा निर्धारण दोनों पक्षों के लिए किसी भी लेन-देन के संदर्भ में समान रूप से लागू होगा ।

5. परिणामतः और उपरोक्त दिए गए कारणों के परिणामस्वरूप 4 फरवरी, 2000 के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता है । तदनुसार, सीपीटी का रद्द अस्वीकार किया जाता है ।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[ विज्ञापन/3/4/143/2000/असा. ]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th August, 2000

**No. TAMP/8/2000-Genl.**—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the representation made by the Calcutta Port Trust against the Order of the Authority dated 4th February, 2000 relating to fixation of penal interest on delayed payments by the users and also penal interest on delayed refunds by the Port Trust, as in the Order appended hereto.

**SCHEDULE****Case No. TAMP/8/2000 – Genl.**

**The Calcutta Port Trust**

...

**Applicant**

**ORDER**

( Passed on this 19th day of July 2000 )

This Authority had passed an Order on 4 February 2000 relating to imposition of 24% interest equally on delayed payment by users and delayed refunds by the Port Trusts. This Order was notified in the Gazette of India, Extraordinary on 23 February 2000 as Gazette No.20.

2.1. The Calcutta Port Trust (CPT) has made a representation against the Order. Arguing that it has no legal validity, the CPT has demanded rescission / withdrawal of the Order with intimation to all the Major Ports.

2.2. The CPT has raised following objections against the Order:

- (i). Sections 112 to 119 under Chapter 9 of the MPT Act deals with imposition of penalties. It has not been prescribed in these Sections that penalties will be attracted for delayed payment.
- (ii). Charging interest in the ordinary course of business is not treated as imposition of penalty. Therefore, the instant Order is out side the purview of the MPT Act.
- (iii). The TAMP is authorised to frame scale of rates and statement of conditions under Section 48 to 51 of the MPT Act. Refund of overcharge is regulated by the provisions of Section 55 of the Act; and, the Board is vested with the power under this Section to remit overcharge made in its bill at any time. There is no time limit for making refunds of overcharges prescribed in Section 55 of the Act.
- (iv). Only the Central Government can give directions to the Board in such matters under Section 111, if necessary at all.
- (v). The condition under which refunds of overcharges will be accepted has also been prescribed under Section 55 of the MPT Act. The conditions incorporated in Section 55 of the MPT Act and the conditions incorporated in the Order of the TAMP are not at par.
- (vi). The order is infringing the provisions of the Act and the powers given to the Board under Section 55 and 129 of the MPT Act.

3. With reference to the totality of information available, and based on a collective application of mind, the following position emerges in respect of the issues agitated by the CPT:

- (i). Sections 112 to 119 of MPT Act (i.e., Chapter X; and, not Chapter – 9, as mentioned by the CPT) deal with imposition of penalties for contravening the provisions of the MPT Act. As correctly pointed out by the CPT, charging interest in the ordinary course of business is not treated as imposition of penalty. The impugned Order speaks about levying of interest during the ordinary course of business.
- (ii). Reference by the CPT to Section 129 of the MPT Act is irrelevant. Section 129 is about application of certain provisions of the Act to aircraft.
- (iii). Section 55 of the Act stipulates a time limit for claiming refund of an over charge made by a Port Trust. The provision under Section 55 reads as follows:

“Provided that a Board may of its own motion remit over charge made in its bills at any time”.

The CPT is perhaps relying on the words ‘at any time’ to base its argument that refund of overcharge can be made by it at any time. The provision under Section 55 is only empowering the Board to decide on refunding the overcharge suo motu, without waiting for an application from a claimant; and, in such a decision the time limit of 6 months may not apply. The CPT’s interpretation of applicability of the words ‘at any time’ to the main Clause of Section 55 is not correct.

- (iv). Just as this Authority can not prescribe anything outside the scope of MPT Act, the CPT can also not charge something not specified by the Act. The CPT is levying a penal interest of 18% on delayed payments of lease rentals. The CPT has included a provision to levy such a penal interest in its schedule of rents for land and building at Haldia.
- (v). This schedule, as proposed by the CPT, has also been approved by this Authority. By proposing inclusion of a provision for penal interest on delayed payments in its schedule of rent, the CPT has recognised that –

— levy of penal interest on delayed payment arises in the context of normal course of business;

— it can be included in the statement of conditions under which its properties are used; and,

— this Authority can make such a prescription.

- (vi). The above referred condition in the Scale of Rates (for land and buildings) of the CPT is applicable only on defaulting tenants / lessees of the CPT’s land. What the impugned Order prescribes is to make such a penalty applicable to both the parties; and, to extend the principle (accepted by the CPT) also to the payments arising in the context of services rendered by the Port Trust and / or use of properties of the Port Trust.
- (vii). It is to be recognised that the intention behind the Order is to prescribe a uniformity of penal interest payable both ways i.e. by Port Users as also by the Port Trusts. In other words, whatever is the time limit or the penal rate of interest prescribed, such prescription will uniformly apply to both the sides relevant to any transaction.

5. In the result, and for the reasons given above, there is no reason to interfere with the Order dated 4 February 2000. Accordingly, the representation of the CPT is rejected.

S. SATHYAM, Chairman  
[ADVT/III/IV/143/2000/Exty.]

2174-61/2000-2

